रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222379
CG-DL-E-12102020-222379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3137] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942
No. 3137] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3549(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि किसी तेल क्षेत्र उद्योग में लगी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 17 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3898(अ), तारीख 30 अक्तूबर, 2019, द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 30 अक्तूबर, 2019, से छह मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी सेवा प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि किसी तेल क्षेत्र उद्योग में लगी सेवाएं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा.सं. एस-11017/1/2018-आईआर (पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2020

S.O. 3549(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest requires that the industry engaged in the services in any oilfield, which is covered under item 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th October, 2019, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3898(E), dated the 30th October, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the industry engaged in the services in any oilfield to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/1/2018–IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.10.12 20:26:25 +05'30'